



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262599
CG-DL-E-23042025-262599

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1774]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2025/वैशाख 1, 1947

No. 1774]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2025/VAISAKHA 1, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2025

का.आ. 1807(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निवार्ध तरीके से सहायकी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकार कहा गया है) के कृषि और किसान कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विभाग कहा गया है) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्य स्तरीय एजेंसियों (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) की एकीकृत स्कीम के अधीन मूल्य समर्थन स्कीम, भावांतर भुगतान स्कीम और बाजार हस्तक्षेप स्कीम लागू कर रही हैं:

और मूल्य समर्थन (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त लाभ कहा गया है) किसानों को उनकी उपज (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त लाभार्थी कहा गया है) को उक्त स्कीम और उसके संबंध में जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अधीन बेचने के लिए दिया जाता है:

और उक्त स्कीम के लिए व्यय भारत की संचित निधि से वहन किया जाता है।

और उक्त एजेंसी इच्छुक है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति के शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित

करने के उद्देश्य से ऐसे लाभार्थी को प्रमाणीकरण कराना या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना या उस व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।"

अतः, अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) [जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 'अधिनियम' कहा गया है] की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. उक्त स्कीम के अंतर्गत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
2. यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो उस दशा में नामांकन के लिए आवेदन करना होगा: यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक की सहमति से ही किया जाएगा।
3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे लाभार्थियों का नामांकन किया जाए जो अभी तक नामांकित नहीं हैं, या उनके आधार विवरण को उचित उपायों के माध्यम से अद्यतन किया जाए, जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित है।

जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, वह निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है जिनके लिए वह पात्र है और जो प्रस्तुति के समय वैध हैं, या, उस सॉफ्टवेयर के मामले में जो उक्त एजेंसी द्वारा प्रदान या अनुमोदित किया गया है ऐसे पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्रमाणित करने के लिए जानकारी प्राप्त करने का समर्थन करता है, संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस से, तो सहमति देकर, अर्थात्:—

उन लाभार्थियों के लिए जिनकी आयु अठारह वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं किया गया है

- (क) लाभार्थी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने पर नामांकन केंद्र में ऑपरेटर द्वारा ईआईडी वाली पावती; और निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज़ जिसमें लाभार्थी की फोटो हो, अर्थात्:—
- (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
- (ii) राशन कार्ड;
- (iii) कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो राजपत्रित अधिकारी है या राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी है जो तहसीलदार के पद से नीचे की पंक्ति का नहीं है, द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र;
- (iv) किसी सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा एक सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी सेवक या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
- (v) भारतीय पासपोर्ट;
- (vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र या अंकपत्र;
- (vii) एक सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा एक सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज़;
- (viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;
- (ix) भारत में जारी चालन अनुज्ञमि;
- (x) देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर

न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान द्वारा रखा गया है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र;

(xi) किसी विदेशी नागरिक की दशा में —

- (I) यदि वह भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक है, तो विदेशी नागरिक का भारत का कार्ड है;
- (II) यदि, वह तिब्बती शरणार्थी है तो विदेशी प्रादेशिक जिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
- (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (IV) यदि वह भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक से भिन्न, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो या तो जिसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा हो या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा हो या

(xii) किसी ऐसे लाभार्थी के संबंध में, जिसके पास विधिक संरक्षक है तो, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क धात, मानसिक मंदता और बहुनिश्चक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 अधिकार अधिनियम या दिव्ययांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साथ्य संबंधी अन्य दस्तावेज़।

(xiii) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

(4) इस संबंध में एजेंसी द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, धारा (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में यह जांच करेगा कि,—

(क) मार्ड आधार पोर्टल (<https://myaadhar.uidia.gov.in/portal>) पर ईआईडी प्रस्तुत करके नामांकन अनुरोध की प्रास्तिकी बावत यह पुष्टि करने के लिए कि ईआईडी वैध है और नामांकन का अनुरोध नामंजूर नहीं हुआ है, और

(ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में, तथा इस प्रयोजन के लिए कि वह ऐसे दस्तावेजों में निहित सूचना को तैयार करने या रखने वाली किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण को प्रस्तुत जानकारी से लिए सहायता ले सकता है तथा साझा कर सकता है।

5. उक्त लाभ लाभार्थियों को आसानी से प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के विषय में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

6. जहां किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे के प्रतिबिंम्ब, उंगलियों की छाप या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से जहां किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता जैसे किसी भी कारण से विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, दिया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक आधारित या वन-टाइम पिन आधारित विधि संभव नहीं हैं, उक्त स्कीम के अधीन लाभ, यथा स्थिति आधार सिक्योर क्रिक रिस्पांस (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़, पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन कर आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकेगा:

(i) आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग कर क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात अर्थात, आधार सिक्योर क्लिक रिस्पांस (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात, आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सूजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है)

(ii) यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात, आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप के सुलभ उपयोग द्वारा किया जा सकता है)।

7. उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, जहां पैरा 1 की धारा (3) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसके संबंध में एक रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी उक्त विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा और संपरीक्षा की जाएगी।

8. एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के बोना फाइड लाभार्थी उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न हों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtibharat.gov.in> पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगी।

9. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-15019/7/2024-एमपीएस (ई-155120)]

सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2025

S.O. 1807(E)—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Central Nodal Agencies like National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited and National Co-operative Consumers' Federation of India Limited through the State level agencies (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the Department of Agriculture and Farmers' Welfare (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering Price Support Scheme, Price Deficit Payment Scheme and Market Intervention Scheme among the components under integrated Scheme of Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas the price support (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the farmers for selling their produce (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India:

And whereas the said agency is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) [hereinafter referred to as the said Act], the Government

of India hereby notifies the following, namely:—

1. An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
2. In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:
Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.
3. In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said agency shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said agency for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

for beneficiaries aged eighteen years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and
- (b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) ration card;
 - (iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) indian passport;
 - (vi) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
 - (ix) driving licence issued in India;
 - (x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (xi) in respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
 - (xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for

Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii) Any other document as the Department may specify.

(4) An officer designated by the Agency in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

5. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

6. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) In cases where biometric-based or one-time pin based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) an Aadhaar Secure Quick Response, (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

7. Notwithstanding anything contained hereinabove, where benefit is given under clause (3) of paragraph 1, a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the said Department.

8. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged eighteen years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Agency shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

9. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. L-15019/7/2024-MPS (e-155120)]
SAMUEL PRAVEEN KUMAR, Jt. Secy.